# शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

राज्य में गत पाँच वर्षों में शिशु मृत्यु दर में कमी का आकलन भारत सरकार के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा कराये गये Sample Registration System के सर्वेक्षण के परिणामों निम्न रेखाचित्र में दर्शाए गए हैं ।

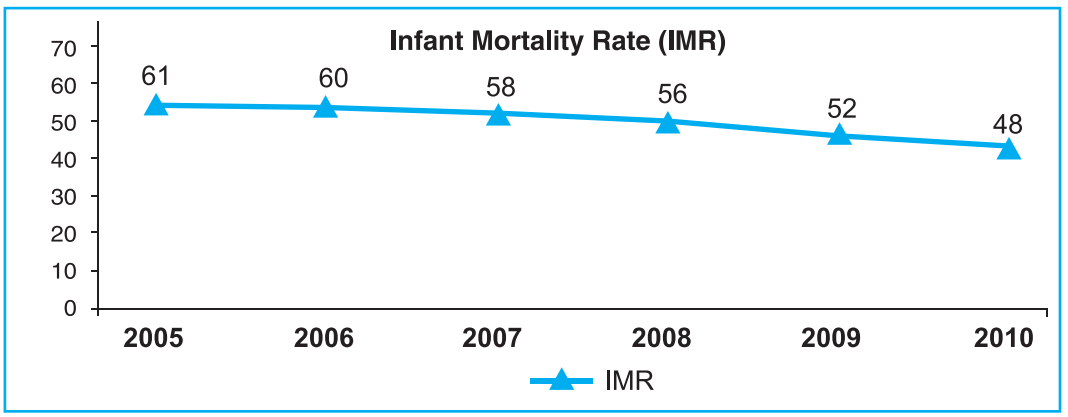


उपर्युक्त रेखाचित्र से परिलक्षित है कि विगत पाँच वर्षों में राज्य में शिशु मृत्यु–दर में लगातार कमी हुई यथा 2005 में शिशु मृत्यु 61 था जो कि कम होकर 2009 में 52 हो गया है ।

राज्य में शिशु मुत्यृ दर को आगामी पाँच वर्षों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर बनाये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को गति प्रदान की जा रही है :

## Integrated Management Neonatal Childhood Illness (IMNCI)

नवजात शिशुओं के समेकित देखभाल के तहत ग्राम स्तर पर IMNCI प्रशिक्षित स्वास्थ कर्मी के द्वारा हुए नए जन्मे शिशु को तीन बार उनके घर पर Post Natal Care दी जा रही है । निम्न ग्राफ

से परिलक्षित होता है कि 1st PNC 55% एवं 3PNC 28% 2009, 2010 में 1st PNC 72% एवं 3PNC 56% में जबकि वर्ष 2011 में सितंबर तक 1st PNC 64% एवं 3PNC 47% माताएं एवं नवजात शिशुओं को सुविधा दी गई है । यह स्वास्थ कर्मी शिशु रोगों के आकलन, पहचान, एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रेफर करने में सक्षम है ।

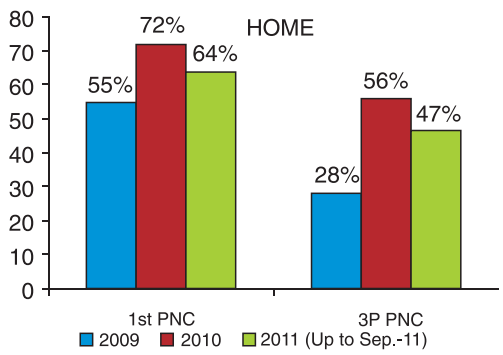


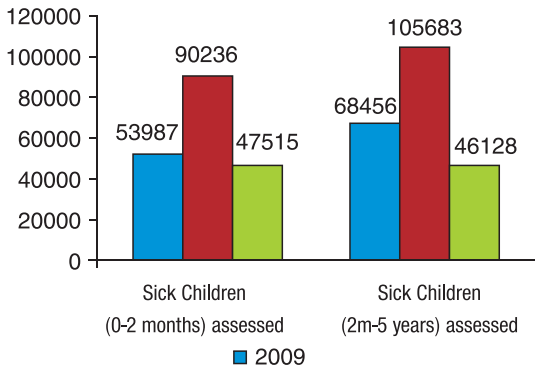


Source: Quarterly Report: Up to sep-2011

## Newborn Care Corner (NBCC)

प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र स्तर पर ''नवजात शिशु कक्ष'' (न्यूबॉर्न कॉर्नर) में नवजात शिशुओं के देखभाल की समुचित व्यवस्था की जा रही है। नवजात शिशु स्वास्थ्य कक्ष के द्वारा बीमार शिशुओं को स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी सेवा प्रदान की जाती है। राज्य के सभी 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर NBCC की स्थापना की जानी है । वर्तमान में 452 ''नवजात शिशु कक्ष'' (न्यूबॉर्न कॉर्नर) कार्यरत है ।

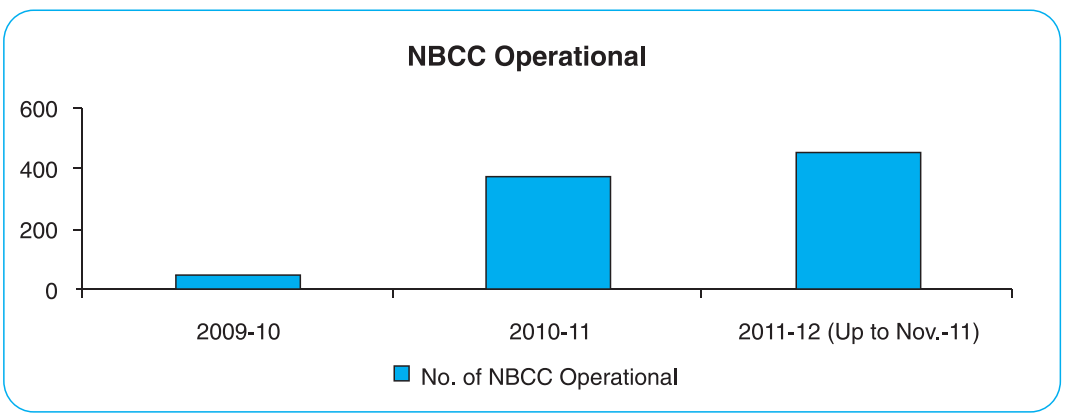


## Newborn Stabilization Unit (NBSU)

राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर NBCC तथा वर्तमान में पूर्व से कार्यरत 76 FRU में से 36 जिला अस्पतालों में SNCU की स्थापना की जा रही है। शेष 40 अनुमंडलीय एवं रेफरल अस्पताल में Newborn Stabilization Unit की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

यह NBSU प्रसूति वार्ड में या प्रसूति वार्ड के निकट स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है । जहाँ पर तुरंत बीमार/कम वजन वाले शिशुओं का उपचार किया जाएगा ।

## Special Newborn Care Unit (SNCU)

स्वास्थ्य सुविधाओं में सुदृढीकरण एवं सुधार हेतु नवजात शिशुओं के लिए जिला अस्पताल में SNCU की स्थापना की जा रही है । जिसके द्वारा बीमार शिशुओं को विशेष सेवा प्रदान की जा रही है ।

वर्तमान में कुल 9 SNCU ''स्पेशल केयर न्यूबॉर्न युनिट (SCNU) कार्यरत है। जिसमें से 6 SNCU जिला स्तर एवं 3 SNCU चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में कार्यरत है। शेष 26 SNCU की स्थापना प्रकियाधीन है ।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुदढ़ीकरण एवं सुधार हेतु नवजात शिशुओं के लिए जिला अस्पताल एवं प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र में एस०सी०एन०यू०/ एन०बी०सी०सी० उपकरण से सुसज्जित नवजात शिशुओं को देखभाल के लिए ईकाई की स्थापना की जा रही है।

06 जिलों यथा वैशाली, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया एवं अररिया जिले में SNCU संचालित है। 23 जिलों में SCNU का निर्माण भारत सरकार के उपक्रम TCIL के द्वारा कराया जा रहा है। 03 जिलों में NIPI द्वारा एस०सी०एन०यू० लेवल–II स्थापित किया जाना है।

## स्तनपान हेतु बढ़ावा

स्तनपान कराना अति आवश्यक यह माँ और बच्चे के बीच लगाव पैदा करता है।

जन्म के बाद प्रत्येक शिशु को माँ गांढ़ा पीला दूध (कोलस्ट्रम) अवश्य देना चाहिए।

शिशु को छः माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएँ।

स्तनपान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न विज्ञापनों (टी०वी० रेडियो, नुक्कड़ नाटक आदि) के माध्यम से प्रत्येक माताओं तक जागरूकता फैलाई जा रही है। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर ममता कार्यकर्ता पदस्थापित हैं ।

जिनके द्वारा प्रसूता माता को नवजात शिशु को जन्म के आधे घण्टे के भीतर एवं छः माह तक सिर्फ स्तनपान कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2009 (स्रोत– युनिसेफ) में 38%, 2010 (स्रोत–

युनिसेफ) में 72% एवं 2011 में नवंबर तक (स्रोत–HMIS) 83% तक बच्चों को जन्म के एक घण्टे के भीतर स्तनपान सुनिश्चित की गई है ।

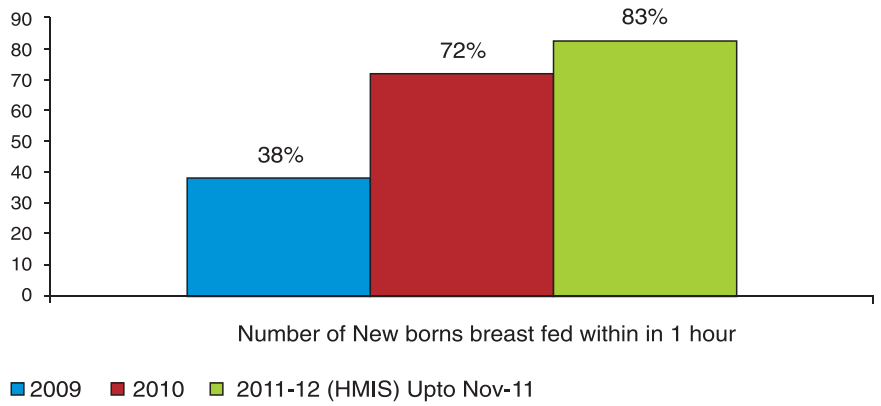


## नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

नवजात शिशुओं को जन्म के समय को निम्नलिखित Basic Resuscitation प्रदान करने हेतु नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) की शुरूआत की गई है ।

- नवजात शिशु का Resuscitation
- जन्म के समय नवजात शिशु की देखभाल
- संक्रमण की रोक–थाम
- तापमान में अंतर से बचाव
- सामान्य एवं कम जन्म भार के शिशुओं की Feeding

इस कार्यक्रम के तहत राज्य स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा जिला स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से जन्म के समय होने वाली जटिलताओं का प्रबंधन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक सुनिश्चित हो पाएगा ।

इसके तहत कुल 156 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है । जिनके माध्यम से गत वर्ष जिला स्तर पर 1823 प्रशिक्षाणार्थियों (चिकित्सक एवं नर्स एवं ए०एन०एम०) को प्रशिक्षित किया जा चुका है । इस वित्तीय वर्ष 2011–12 में जिला स्तर तक कुल 5460 चिकित्सकों, नर्सों/ए०एन०एम० को प्रशिक्षित किया किये जाने का लक्ष्य है । इस वर्ष प्रशिक्षण दिसंबर माह–11 से प्रारंभ की गई है एवं कुल 90 प्रशिक्षाणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और जिसे संभवतः वित्तीय वर्ष के अंत तक सम्पन्न कर ली जाएगी ।

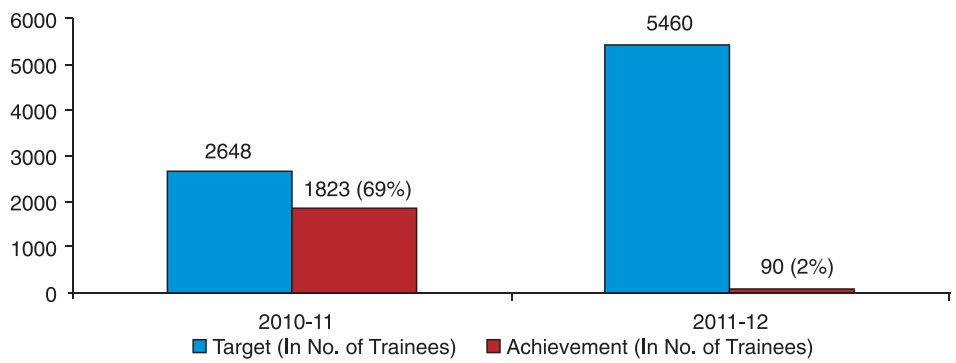

# नियमित टीकाकरण

राज्य में नियमित टीकाकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित हुई है। इसके अन्तर्गत बचपन में होने वाली बीमारियों में 7 ऐसी जानलेवा बीमारियॉ है जिनसे नियमित टीकाकरण द्वारा बचाव संभव है। ये बीमारियॉ है – पोलियो, खसरा, गलघोंटू, काली खाँसी, टीबी, टिटेनस एवं हेपटाइटिस–बी।

टीकाकरण हेतु ए.एन.एम., आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं एवं आशाओं को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की गई। सप्ताह के प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार को टीकाकरण दिवस घोषित किया गया तथा सभी आँगनवाड़ी केन्द्रों सहित दूर – दराज के क्षेत्रों तथा महादलित टोलों में टीकाकरण सत्र आयोजित करने के उद्देश्य से कार्ययोजना विकसित की गईं।

वर्ष 2007 बिहार के नियमित टीकाकरण में एक महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि इस वर्ष कार्यक्रम को गति प्रदान करने के उद्देश्य से मुस्कान एक अभियान कार्यक्रम शुभारम्भ किया गया। शहरी क्षेत्र में भी टीकाकरण की शुरूआत की गई। इन सबके **फलस्वरूप राज्य में सम्पूर्ण प्रतिरक्षण का प्रतिशत् बढ़कर वर्ष 2009 में 54 प्रतिशत् एवं वर्ष 2010–11 में कराये गये सर्वेक्षण में 66.8 प्रतिशत हो गया है। यह राष्ट्रीय औसत 61 प्रतिशत से अधिक है।**

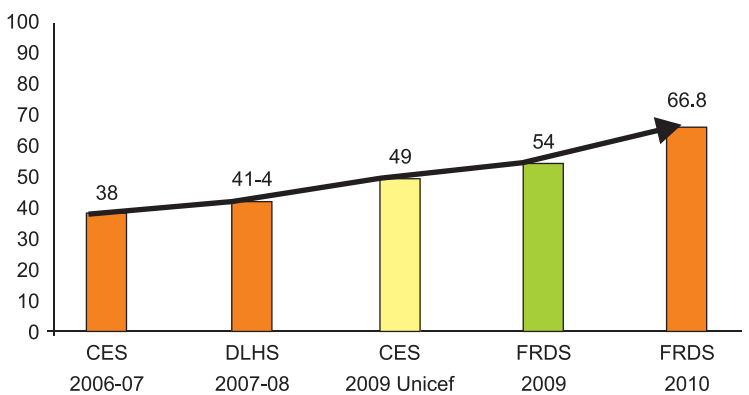


राज्य में शिशु मृत्यु दर एवं पोलियो के मामले में कमी आने के प्रमुख कारणों में नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम का सुदृढ़ होना भी है। नियमित टीकाकरण द्वारा राज्य में लगभग कुल 30 लाख गर्भवती महिलाओं एवं लगभग 28.5 लाख नवजात शिशुओं का टीकाकरण किया जाता है।

हेपटाइटिस–बी वैक्सिन को अक्टूबर 2011 में राज्य में पहली बार सभी जिलो में उपलब्ध कराया गया है।

वर्ष 2011–12 में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की निम्नांकित उपलब्धियाँ रही हैं :–

- सभी सत्रों पर कुरियर के द्वारा वैक्सिन को पहुँचाना
- राज्य के 92 प्रतिशत या इससे अधिक सत्रों पर नियमित रुप से टीकाकरण सत्र का सम्पन्न होना
- सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर माह में एक सत्र अवश्य होना
- प्रत्येक दो माह के अन्तराल पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारियों की राज्य स्तर पर समीक्षात्मक बैठक होना
- सिविल सर्जन की अध्यक्षता में प्रत्येक सप्ताह जिला स्तर पर समीक्षात्मक बैठक होना
- प्रत्येक माह स्वास्थ्य विभाग एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन–एन.पी.एस.पी. द्वारा 3500 से अधिक सत्रों की मॉनिटरिंग किया जाना
- आयुष चिकित्सकों को नियमित टीकाकरण हेतु प्रशिक्षित किया जाना
- सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर नया मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाना
- गया, पश्चिम चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त तीन अन्य जिलों यथा सिवान, नवादा एवं गोपालगंज में 16–24 माह के बच्चों के लिए जापानी इन्सेफलाइटीस के टीके का शुभारम्भ

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 को सघन नियमित टीकाकरण वर्ष (Year of Intensification of Routine Immunization) घोषित किया गया है। इसके अन्तर्गत, सभी जिलों में पूर्ण टीकाकरण 80% या उससे अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि राज्य के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रत्येक महीने टीकाकरण का एक सत्र किया जाता है, आई.सी.डी.एस. निदेशालय से भी सामंजस्य स्थापित किया गया है ताकि इस लक्ष्य की ससमय प्राप्त हो सके।